गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 165
दि. 14.10.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा – सत्ता का दुरुपयोग कर रची गई साजिश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तथा उनके पुत्र और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत सबूतों के आधार पर यह पाया गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मुकदमे की औपचारिक सुनवाई अब शुरू की जाएगी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर अनियमितता को बढ़ावा दिया और अपने परिवार को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए षड्यंत्र रचा। अदालत के अनुसार, आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित होटलों के रखरखाव से जुड़े टेंडर की प्रक्रिया में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि लाभ लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिल सके।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने और निजी लाभ हासिल करने के लिए यह षड्यंत्र 2004 से 2009 के बीच रचा गया, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। अदालत ने यह भी पाया कि इस सौदे के तहत कोचर परिवार से बेहद कम कीमत पर जमीन खरीदी गई, जिसे बाद में राबड़ी

देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर स्थानांतरित किया गया।

अदालत ने तीनों नेताओं से पूछा कि क्या वे लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं। इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों ने खुद को निर्दोष बताया और सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया।

सीबीआई ने अदालत में इस मामले से संबंधित कई गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने दावा किया कि लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर आईआरसीटीसी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और अपने परिवार की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित रूप से ठेका दिलवाया।

अदालत ने आदेश दिया है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मुकदमा चलेगा। भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच एक सुनियोजित साजिश के तहत आईआरसीटीसी के दो होटलों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। निविदा की शर्तें इस प्रकार तैयार की गईं कि ठेका सुजाता होटल्स और उससे जुड़ी कंपनियों को मिले।

मामले में आईआरसीटीसी के पूर्व अधिकारी वी.के. अस्थाना, आर.के. गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर, विनय कोचर और डिलाइट मार्केटिंग (अब लारा प्रोजेक्ट्स) समेत कुल 14 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

तेजस्वी यादव ने अदालत के आदेश के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "यह सब राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। चुनाव से पहले हमें फंसाने की साजिश रची जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक महीने पहले कहा था कि तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। आज जो कुछ हो रहा है, वह उसी धमकी का परिणाम है।" तेजस्वी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी कानून में विश्वास रखती है, लेकिन "सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है।" उन्होंने दावा किया कि आईआरसीटीसी का यह टेंडर पूरी तरह पारदर्शी था और इससे रेलवे को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ।

वहीं, सीबीआई का पक्ष है कि जांच एजेंसी ने ठोस दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड के माध्यम से साबित किया है कि यह सौदा "क्विड प्रो क्वो" (लेन-देन के बदले लाभ) के सिद्धांत पर आधारित था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है।

लालू परिवार पहले से ही कई भ्रष्टाचार मामलों का सामना कर रहा है, और अगर इस मामले में दोषसिद्धि होती है, तो यह 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की रणनीति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

मामले की अगली सुनवाई अब नवंबर के पहले सप्ताह में होगी, जब अदालत सीबीआई के प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अदालत ने सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

आईआरसीटीसी घोटाला, जिसने कभी भारतीय राजनीति को झकझोर दिया था, अब एक बार फिर से उसी बिंदु पर लौट आया है जहाँ कानून और राजनीति आमने-सामने खड़ी हैं — एक ओर सीबीआई की कानूनी दलीलें और दूसरी ओर लालू परिवार का यह दावा कि यह सब "राजनीतिक प्रतिशोध" की कहानी है।

मेडागास्कर में जेन-ज़ेड की बगावत: राष्ट्रपति राजोएलिना देश छोड़कर भागे, सेना पर तख्तापलट का आरोप

(जीएनएस)। हिन्द महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय देश मेडागास्कर में पिछले हफ्ते से चल रहे युवाओं के उग्र विरोध-प्रदर्शन ने देश की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। राजधानी एंटानानारिवो में हजारों युवा जेनरेशन-ज़ेड के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और पानी, बिजली की कमी, बेरोज़गारी और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की। सोमवार को राष्ट्रपति आंद्रे राजोएलिना अचानक देश छोड़कर भाग गए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुरोध पर उन्हें एक फ्रांसीसी सैन्य विमान के जरिए सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया।

राजोएलिना ने रविवार को दावा किया था कि सेना के भीतर तख्तापलट की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सोमवार को स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राष्ट्रपति को तत्काल देश छोड़ना पड़ा। राजधानी के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में युवाओं को सरकारी भवनों पर कब्जा करते और "जनता की आवाज़" के नारे लगाते देखा गया। राजोएलिना का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों से भरा रहा है। वे पहली बार 2009 में सेना की मदद से सत्ता पर आए थे, 2014 में पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2018 में चुनाव जीतकर फिर से राष्ट्रपति बने और 2023 में एक विवादित मतदान में तीसरा कार्यकाल हासिल किया। इस बार की बगावत में सेना की एक विशेष इकाई कैपसैट, जिसने 2009 में उन्हें सत्ता तक पहुँचाया था, अब उनके खिलाफ

खड़ी हो गई और प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही है।

आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मेडागास्कर संकटग्रस्त है। विश्व बैंक के अनुसार देश में पांच में चार लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाएँ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने युवाओं में गुस्सा बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुराना तंत्र समाप्त नहीं होता, वे पीछे नहीं हटेंगे।

इस विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत पिछले महीने पानी और बिजली की भारी कमी के कारण हुई थी। युवाओं की सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक कम से कम 22 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। राजधानी में आपातकाल लागू है, इंटरनेट बंद है और कर्फ्यू लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ ने संयम बरतने की अपील की है, लेकिन युवा प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सत्ता में बदलाव के लिए पीछे नहीं हटेंगे।

मेडागास्कर की यह बगावत विश्व के कई देशों में हाल ही में हुई जेन-ज़ेड की राजनीतिक सक्रियता का हिस्सा बन गई है। नेपाल, इंडोनेशिया, केन्या और मोरक्को में भी इसी पीढ़ी ने सरकारों को चुनौती दी थी। यहां युवाओं का नारा स्पष्ट है—"हम न्याय चाहते हैं और सत्ता का पुराना तंत्र समाप्त होना चाहिए।"

भारत-कनाडा संबंधों में नई दिशा: खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती और सहयोग का विस्तृत खाका

(जीएनएस)। दिल्ली में सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात ने भारत-कनाडा संबंधों को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इस बैठक को न केवल द्विपक्षीय सहयोग के पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि यह खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के खिलाफ भारत के सख्त रुख का स्पष्ट संकेत भी है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव, खासकर कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता को लेकर भारत की चिंताओं के बीच यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जयशंकर ने बैठक के बाद अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और कनाडा के बीच संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश साझेदारी को और गहराई देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बैठक केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि 26 मई को हुई पिछली टेलीफोन वार्ता के बाद से जारी संवाद का ठोस विस्तार थी। पिछले दो महीनों में दोनों देशों ने कई स्तरों पर वार्ताएँ की हैं और यह तय किया है कि वे पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे। जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रियों के रूप में दोनों देशों की ज़िम्मेदारी है कि वे सहयोग के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करें और सुनिश्चित करें कि यह उनके प्रधानमंत्रियों की अपेक्षाओं और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस सहयोग का अर्थ केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सरकारों के समग्र कार्यक्षेत्र में व्यापक संवाद और समन्वय का

हिस्सा होना चाहिए।

बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चर्चा खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और कनाडा में भारत विरोधी बयानों को लेकर रही। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे तत्वों को खुली छूट देना दोनों देशों के संबंधों पर गहरा असर डाल रहा है और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह चर्चा कनाडा सरकार के लिए भी एक सख्त संदेश मानी जा रही है कि भारत अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं करेगा। जयशंकर ने इस बैठक को "नई साझेदारी का रोडमैप" बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनाई है। इसके साथ ही असैन्य परमाणु सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा क्षेत्र में भी संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह सहयोग न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करेगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता लाने में भी योगदान देगा।

जयशंकर ने कहा कि भारत-कनाडा की नई समझदारी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 'जोखिम मुक्त' बनाना है। दोनों देशों के बीच बढ़ता संवाद और आपसी विश्वास आने वाले वर्षों में व्यापारिक संबंधों के साथ-साथ सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में भी नए अवसर खोलेगा। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि दोनों देशों के उच्चायुक्त अब अपनी-अपनी राजधानियों में कार्यभार संभाल चुके हैं और उन्होंने आज की बैठकों में भाग लेकर इस सहयोग की दिशा को और स्पष्ट किया है। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत अपने वैश्विक साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संतुलन की नई परिभाषा गढ़ रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक नीति निर्धारण का सक्रिय भागीदार है। खालिस्तान समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा के साथ-साथ यह बैठक इस बात का संकेत भी है कि भारत कनाडा के साथ अपने संबंधों को वैचारिक मतभेदों के बावजूद आगे बढ़ाना चाहता है — लेकिन समान सम्मान और परस्पर विश्वास के आधार पर।

ट्रम्प के संदेश से मध्य-पूर्व में नई उम्मीद: बंधकों की रिहाई, शांतिपूर्ण विकल्प और वैश्विक संतुलन की पुकार

(जीएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यरूशलम में दिया गया भाषण उस समय की साफ़ ऐतिहासिक छाप छोड़ गया जब कई वर्षों से जारी विनाशकारी गठरी—गाज़ा संघर्ष—के बीच एक अहम मोड़ आया। ट्रम्प ने न केवल इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा मध्यस्थता कराए गए युद्धविराम समझौते की खुले दिल से सराहना की, बल्कि उन 20 इज़राइली बंधकों की सुरक्षित रिहाई को क्षेत्र में "बड़े बदलाव" का संकेत बताया जिसने लंबी पीड़ा झेल रहे लोगों के लिए राहत की सांस बनकर काम किया। उनके शब्दों में वह क्षण भविष्य की कई पीढ़ियों के लिए वह पल बन जाएगा जब सब कुछ बेहतर हुई दिशा में बदलना शुरू हुआ। समझौते के हिस्से के रूप में इज़राइल ने 1,900 से अधिक फ़िलिस्तीनियों में से कुछ कैदियों की रिहाई की प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया। मिस्र के एक अधिकारी की जानकारी के अनुसार, 154 रिहा किए गए फ़िलिस्तीनी कैदियों को मिस्र भेजा गया, जबकि अन्य कैदी गाज़ा पहुँचने लगे। यह रिहाई उन समझौतों के तहत हो रही है जिनमें बचे हुए बंधकों की आज़ादी सुनिश्चित करने के ऐतिहासिक प्रयास शामिल हैं। ऐसे संवेदनशील परिवहन और शिफ्टिंग कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है कि ज़्यादातर बार इसमें प्रत्यक्ष संचार सीमित और गुप्त रखा जाता है—इसीलिए उन अधिकारियों ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर यह सूचना साझा की। ट्रम्प ने यरूशलम में अपने संबोधन में फ़िलिस्तीनियों से भी स्पष्ट संदेश दियाः "आतंकवाद और हिंसा से दूर रहें।" उनका कहना था कि फ़िलिस्तीनी समाज के लिए विकल्प अब और स्पष्ट नहीं हो सकता—या तो हिंसा का मार्ग जो विनाश

और दुःख लेकर आता है, या फिर शांति का रास्ता जो स्थायी विकास और बेहतर जीवन का मार्ग खोलता है। ट्रम्प ने इसे फ़िलिस्तीनियों के लिए एक मौक़ा बताया—ऐसा अवसर जब वे आतंक और हिंसा से हमेशा के लिए दूरी बनाकर तरक्की और रोज़गार जैसे सकारात्मक विकल्प चुन सकते हैं। अपने भाषण के दौरान ट्रम्प ने नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे आरोपों का भी संदर्भ दिया और इज़राइली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से अपील की कि वे आरोपों के बावजूद राष्ट्रीय हित और वर्तमान ऐतिहासिक घड़ी को देखकर परिस्थिति को संभालें—"सिगार और थोड़ी शैंपेन—किसे परवाह है?" जैसा उनके तर्ज़ुमान में वह कहा करते हैं—मतलब व्यक्तिगत आरोपों की पृष्ठभूमि में भी राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ और सुरक्षा के मसले सर्वोपरि होने चाहिए। ट्रम्प का संदेश सिर्फ़ इज़राइल और फ़िलिस्तीन तक सीमित नहीं रह गया। उन्होंने ईरान, रूस और चीन जैसे देशों को भी नसीहत दी कि वे हथियारों के निर्माण और आर्म्स रेस में निवेश करने की बजाय अपनी वित्तीय और बौद्धिक संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर लगाएं। उनका तर्क था कि यदि देश स्कूल, अस्पताल, उद्योग और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में खर्च बढ़ाएँगे तो वहां के नागरिकों को सच्चा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय द्वेष घटेगा। ट्रम्प ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों को एक-दूसरे को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए और मिलकर तरक्की के मौक़ों पर काम करना चाहिए—यही स्थिरता और समृद्धि का पथ है। यह बयान एक व्यापक राजनीतिक संदेश भी था—यह संकेत कि वैश्विक शक्तियाँ केवल शक्ति प्रदर्शित करने में नहीं, बल्कि स्थायी विकास और मानवीय कल्याण पर निवेश करके ही दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। ट्रम्प ने उस समय की महत्वाकांक्षा जताई कि अगर वैश्विक खिलाड़ी हथियारों के बजाए शिक्षा और चिकित्सा पर पैसा लगाती हैं तो दुनिया के कई हिस्सों में तंगी और तनाव घटेंगे। कठिन और संवेदनशील कूटनीति के इन पलों में, बंधकों की रिहाई और कैदियों का आदान-प्रदान केवल सैन्य या रणनीतिक सफलता नहीं माना जा सकता—यह भावनात्मक, मानवीय और राजनैतिक स्तर पर भी एक संकेत है कि बातचीत व मध्यस्थता से बड़े गतिरोधों को तोड़ा जा सकता है। मिस्र के माध्यम से कैदियों की सुरक्षित ढुलाई, गाज़ा पहुँचने वाले फ़िलिस्तीनी नागरिक और ट्रम्प का सार्वजनिक समर्थन—ये सभी घटनाएँ इस बात की दास्तान सुनाती हैं कि अंततः राजनैतिक इच्छाशक्ति और अंतरराष्ट्रीय दबाव के मिश्रण से संघर्ष का नरम पड़ाव संभव है। हालाँकि ऐसी सफलता क्षणिक या सीमित भी हो सकती है—ऐसे समझौतों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन पर टिकाऊ निगरानी, लागू करने की पारदर्शिता और स्थानीय नेताओं के बीच वास्तविक समझ बने रहे।

नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका: पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट मामले में राहत नहीं मिली

(जीएनएस)। गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर

दर्ज FIR के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने स्पष्ट किया कि इस चरण पर वह हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इस तरह नेहा की याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच जारी रहेगी। यह विवाद उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है जो नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया था। आरोप है कि इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। नेहा ने FIR को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल मामले की जांच पूरी होने तक कोई राहत नहीं दी जा सकती। यूपी पुलिस ने नेहा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 की धारा 196, 197, 152, 353 और आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में इसमें देशद्रोह से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गईं। नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उन्हें 'देश के खिलाफ साजिश' जैसी गंभीर धाराओं में फसाना गलत है। नेहा के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि वह ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन पर बगावत जैसी धाराएं नहीं लगनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की दलीलें वह ट्रायल या चार्ज फ्रेमिंग के समय रख सकती हैं। इस फैसले के साथ यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा और मामले की जांच पूरी होने तक नेहा को राहत नहीं मिलेगी। इस कदम से यह भी संकेत मिलता है कि सोशल मीडिया पोस्ट और उस पर की गई टिप्पणियों के मामलों में भारतीय न्यायालय सख्त रुख अपना रहा है, खासकर जब सुरक्षा और देशभक्ति से जुड़े आरोप शामिल हों। नेहा सिंह राठौर के लिए यह न केवल कानूनी चुनौती है, बल्कि उनके सार्वजनिक छवि और भविष्य की मीडिया गतिविधियों के लिए भी एक चेतावनी के समान है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमाओं और कानूनी दायरे में ही सुरक्षित रहती है।

संपादकीय

कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित

लगातार ग्लोबल वार्मिंग संकट से जूझती दुनिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। केंद्र सरकार के गत सप्ताह की शुरुआत में अधिसूचित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, भारत में औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा रहा है। इन नियमों ने कार्बन-प्रधान उद्योगों के लिये देश के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनतम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐसे में, जो उत्पादन इकाइयां अपने निर्धारित लक्ष्य से कम कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, वे व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली इकाइयों को भारतीय कार्बन बाजार से समतुल्य क्रेडिट खरीदना होगा या फिर जुर्माना देने को बाध्य होना होगा। दरअसल, एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी एवं कागज आदि क्षेत्रों की 282 औद्योगिक इकाइयों को 2023-24 के आधार रेखा स्तर से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पहले अनुपालन चक्र में कुछ बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को और बाल्को द्वारा संचालित एल्युमीनियम स्मेल्टर और अल्ट्राटेक, डालमिया, जे.के सीमेंटे,श्री सीमेंट और एसीसी के स्वामित्व वाले बड़े सीमेंट संयत्र शामिल हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है कि बड़े औद्योगिक घरानों को हरित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अनुकरणीय उदाहरण पेश करना होगा। यदि ये ताकतवर बड़े घराने हरित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सार्थक पहल करते हैं तो आम लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। जिसमें चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। निस्संदेह, नये नियम, जो उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिये प्रोत्सहित करते हैं, उनके औद्योगिक प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार ऊर्जा दक्षता योजना पर आधारित हैं। जिसने ऊर्जा-बचत के लक्ष्य निर्धारित किए। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे दंड लगाने और समयबद्ध निगरानी व वसूली का काम सौंपा गया है, को कानूनी ढांचे के अनुसार सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता है। इस बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े औद्योगिक दिग्गजों के प्रतिरोध के लिये पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। यह बात उत्साहजनक है कि भारत ने इस वर्ष पहली छमाही में पहले से कहीं अधिक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन किया। जबकि इस अवधि के दौरान भारत के बिजली क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में साल-दर-साल आधार पर एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों को जलवायु परिवर्तन का सबसे अहम कारक माना जाता है। हमारा देश, जिसने इस वर्ष ही जलवायु प्रभाव संबंधी आपदाओं की बाढ़ देखी है, को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। निस्संदेह, सतत विकास - जलवायु के प्रति संवेदनशीलता कार्बन-तटस्थ भविष्य की ओर बढ़ने के अनुरूप होना चाहिए।

अफ़ग़ान महिलाओं के अधिकारों का यक्ष प्रश्न

> अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के दौरे के दौरान तालिबान शासन के प्रति भारत की नीति में बेहतर व अहम बदलाव के संकेत मिले हैं। हालांकि वहां महिलाओं के अधिकारों खासकर शिक्षा व समानता जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना जरूरी है।

'क्या आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं'? यहां कोई गलती न रहे, यह महज एक 'गुगली' है, न कि एक सवाल, जो सालों से उत्तर भारतीय महिलाओं से पूछा जाता रहा है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि अगर आप रखती हैं तो आपका मजाक बनाया जाएगा (नारीवादियों द्वारा कनखियों से देखते हुए) या अगर नहीं रखती हैं तो भी हिकारत से देखा जाएगा (मध्य वर्गीय भारत के बढ़ते संस्कृतिकरण की वजह से, जिसका मानना है कि किसी भी पहेली का सिर्फ़ एक ही जवाब हो सकता है), बल्कि इसलिए कि यह सवाल अपने आप में संकुचित है। इस पर चुप्पी साधना बेहतर। बढ़िया रहेगा कि रूही तिवारी द्वारा हाल ही में लिखी गई किताब 'महिलाएं क्या चाहती हैं' पढ़ें।

सुश्री तिवारी की किताब भारत में 'महिला मतदाता को समझने' के बारे में है, लेकिन सवाल का परिदृश्य बृहद है। अगर आपमें कल्पनाशीलता है, तो आप इसके दायरे को और भी व्यापक बना सकते हैं, जिसमें पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान भी शामिल है, जहां का तालिबान शासन अपनी ही महिलाओं के ख़िलाफ़ सबसे दमनकारी कार्रवाइयां चलाए हुए है। दरअसल, दिल्ली से खबर आई थी कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, जो भारत के छह दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वे प्रेम के प्रतीक ताजमहल और देवबंद मदरसे का भी दौरा करेंगे, पर उन्होंने बीते शुक्रवार को राजधानी में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी भारतीय महिला पत्रकार की मौजूदगी पर रोक लगा दी।

शायद मुत्ताकी को इस बात की चिंता थी कि उन्हें भारतीय महिलाओं के साथ वार्तालाप करते देख स्वदेश में क्या संदेश जाएगा। भले ही प्रेस वार्ता अफ़ग़ान दूतावास में हुई थी, जोकि तकनीकी रूप से अफ़ग़ानिस्तान की धरती है, तालिबान नेता ने अपने देश की आधी आबादी को यह संकेत देने का एक बड़ा मौका गंवा दिया कि अफ़ग़ानिस्तान के इस्लामी अमीरात को अंधकारमय युग से बाहर निकलने का एक

और छोटा-सा मौका क्यों दिया जाना चाहिए। क्या पता, भारतीय महिला पत्रकार मुत्ताकी से ऐसा कुछ पूछ बैठतीं जिसका उनके पास कोई जवाब न होता : मसलन, अफ़ग़ान महिलाएं क्या चाहती हैं? और अगर उनकी हसरत अपना हक पाने भर की है, तब कंधार के मुल्ला उन्हें वह क्यों नहीं देते? लेकिन, अगर आप वाकई देखना चाहें, तो तमाम जवाब मौजूद हैं। यह लेखिका अगस्त 2022 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्ज़ा किए जाने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर वहां मौजूद थी, और इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय के आईसीयू में यह देखने गयीं कि महिला नर्सें और डॉक्टर सबसे कठिन मामलों से कैसे निबटते हैं। आईसीयू साफ़ और सैनिटाइज़्ड था। महिला डॉक्टरों और नर्सों ने वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे ढके हुए नहीं। वहां वे जान बचाने को थीं, खासकर जिंदगी की लड़ाई लड़ते नवजात शिशुओं की, इसलिए नहीं कि वे महिला थीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास ये कौशल, विशेषज्ञता व प्रतिबद्धता थी।

दिल्ली में, निश्चित रूप से, भारत और अफ़ग़ान शासन, महिला पत्रकारों को दूर रखने के मामले को रफा-दफा कर इस पर विवाद न्यूनतम रखना चाहेंगे और सभी से चीज़ों को व्यापक परिदृश्य के मुताबिक देखने का आग्रह करेंगे- यानी भारत तालिबानों के रवैये को लेकर अपने एतराजों से पीछे हट चुका है और अब काबुल में अपने राजनयिक मिशन को पूर्ण दूतावास में अपग्रेड करेगा। यह न केवल पड़ोस को लेकर भारत की नीति में वाकई बड़ा कदम, बल्कि व्यावहारिकता की ओर स्वागत योग्य वापसी का संकेत भी है।

दुःखद यह कि अफ़ग़ानिस्तान के मामले में अपनी गलतियों को समझने में भारत सरकार को करीब एक दशक लग गया। भारत ने अमेरिकियों, खासकर काबुल में अफ़ग़ान मूल के पूर्व अमेरिकी राजदूत ज़ल्माय खलीलज़ाद से अति प्रभावित होकर भुला दिया कि इस क्षेत्र में उसकी स्थिति कितनी मज़बूत है। होना चाहिए था कि अमेरिका भारत के इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य व मौजूदा विश्लेषणों पर निर्भर रहता, जबकि हुआ उलट। अफगान परिदृश्य में सत्ता वितरण में भारत को भूमिका निभानी चाहिए थी - सबसे पहले, हामिद करज़ई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच सत्ता संघर्ष सुलटाने में मदद करके; फिर जब अशरफ़ ग़नी को अमेरिकी स्थापित कर रहे थे, तो उन्हें बताना चाहिए था कि यह गलत निर्णय है; लेकिन जब ग़नी काबुल की गद्दी पर बैठ ही गए, तो भारत को चाहिए था कि उभरते तालिबान के ख़िलाफ़ एक गठबंधन बनाने में मदद करे, सभी पक्षों में समझौता कराने को उदारवादी तालिबान से भी बात कर सकता था। इस बीच दिल्ली में चर्चा चली कि देखा भारत ने कितनी चतुराई से तालिबान को अपने पाले में कर लिया है! जबकि विडंबना है कि तालिबान तो बहुत पहले से भारत के साथ आने को तैयार था। काबुल या अफ़ग़ानिस्तान में किसी भी तालिबान परस्त या गैर-तालिबान अफ़ग़ान से बात कीजिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला, पश्तून, ताजिक या हज़ारा, तो आपको अफ़ग़ानों में भारतीयों के प्रति अविश्वसनीय स्नेह-सम्मान महसूस होगा। करवा चौथ या ऐसे दृश्यों से इतर, बॉलीवुड के नायक और नायिकाएं आज भी वहां बहुत लोकप्रिय हैं।

यह न भूलें कि तालिबान भी अफ़ग़ान हैं - हामिद करज़ई से यदि बात करें तो वे आपको हर बार इस मूल सच की याद दिलाते हैं। इसका अहम पहलू यह कि वास्तव में उन्हें अरबों के रहमो-करम पर रहना मंजूर नहीं। यह सवाल कि ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा की पहाड़ियां छोड़ एबटाबाद में, पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान से चंद कदम दूर, रहने क्यों आया, इसके अपने जवाब हैं।

सच तो यह कि भारतीय विदेश मंत्रालय मौजूदा स्थिति पर पहुंचने को कई जटिल मोड़ों से गुज़रा - यानी भारत व अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराना ख़ास रिश्ता है। यहां, दूसरा सच है : भारत अपने ही पास-पड़ोस से दूर हो गया और दूसरे देशों को बढ़त पाने का मौका दिया। चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब अहम खिलाड़ी हैं –काराकोरम पर्वत शृंखलाओं से लेकर हिंद महासागर तट पर कॉक्स बाज़ार तक फैले, इन सभी देशों से बने इलाके में - जहां उनकी भूमिका का स्वागत है वहीं दूसरी ओर भारत को इस क्षेत्र में अपने प्रमुख स्थान पर लौटना होगा।

आमिर ख़ान मुत्ताक़ी की मेज़बानी कर पहला कदम उठाया जा चुका है। दूसरा होना चाहिए, हेरात, जलालाबाद, कंधार और मजार-ए-शरीफ स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास फिर खोलना - जिन्हें किसी न किसी बहाने बंद कर दिया था, पहले ज़्यादातर अमेरिकी दबाव में और बाद में, 2021 में तालिबान के कब्ज़े के डर से।

कदाचित्, विदेश मंत्रालय को अपनी कुछ बेहतरीन महिला राजनयिकों को इन वाणिज्य दूतावासों में तैनात करना चाहिए, ठीक वैसे जैसा 2001 में किया गया था जब अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान मामलों को देखने वाली तेजतर्रार राजनयिक विजय ठाकुर सिंह को 9/11 के हमलों के बाद, अमेरिका द्वारा तालिबान को बमबारी कर घुटनों पर लाने के बाद के काल में, काबुल भेजा गया था– उनके साथ गौतम मुखोपाध्याय, रुद्रेंद्र टंडन के अलावा बतौर भारतीय राजदूत विवेक काटजू थे; काटजू इन दिनों द ट्रिब्यून के स्तंभकार भी हैं, वे दिसंबर 1999 में उस टीम का हिस्सा भी थे, जिसने आईसी-814 के यात्रियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए कंधार की हवाई पट्टी पर हफ़्ताभर तालिबान के साथ मोल-तोल किया था। कौन कहता है कि भारत तालिबान को नहीं जानता? काबुल में एक भारतीय राजदूत की नियुक्ति कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो घर जाने जैसा है। मुत्ताक़ी को यह बात उन सभी भारतीय पुरुष और महिला पत्रकारों से कहनी चाहिए थी जिन्हें वे शुक्रवार को दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करते -और 'महिलाएं क्या चाहती हैं' इस प्रश्न समेत तमाम सवालों का धैर्यपूर्ण जवाब देते।

'नाश्ता दिल्ली में, दोपहर का भोजन अमृतसर में (अगर आप लाहौर नहीं जा सकते) और डिनर काबुल में'? जैसे ही डॉ. मनमोहन सिंह का यह मशहूर कथन फिजा में गूंजने लगता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कहीं बैठे विजयी हंसी हंस रहे होंगे कि जो लोग कभी उनकी जिस नीति का मखौल उड़ाया करते थे, आज खुद वही करना पड़ रहा है।

प्रेरणा

हाजिरजवाबी की शक्तिः जब किसान की बुद्धि ने देवियों के विवाद का अंत किया

बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्गलोक में देवी-देवताओं के बीच विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ करता था। एक दिन लक्ष्मी देवी और दरिद्रता देवी के बीच एक बड़ा ही विचित्र विवाद खड़ा हो गया। दोनों देवियाँ अपने सौंदर्य और प्रभाव को लेकर आपस में बहस करने लगीं। लक्ष्मी देवी, जो धन, ऐश्वर्य, वैभव और सुख की अधिष्ठात्री थीं, गर्व से बोलीं — "संसार में मुझसे सुंदर कोई नहीं। मैं जिस घर में प्रवेश करती हूँ, वहाँ हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और सौभाग्य का वास हो जाता है। मेरे आने से चेहरों की चमक लौट आती है और हर दिशा मुस्कुराने लगती है।"

दरिद्रता देवी ने उत्तर दिया — "तुम्हारा सौंदर्य केवल धनवानों के घर तक सीमित है, जबकि मेरा प्रभाव संपूर्ण है। मैं जब किसी के घर आती हूँ, तो उसका गर्व मिट जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। मेरे प्रभाव से मनुष्य विनम्र बनता है, उसे संयम का पाठ मिलता है। इसीलिए मेरा सौंदर्य गहरा है, स्थायी है, और जीवन के अनुभव से जुड़ा है।"

दोनों देवियाँ अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करती रहीं। लक्ष्मी देवी के चेहरे पर तेज और गौरव झलक रहा था, वहीं दरिद्रता देवी के स्वर में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुईं। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा — "चलो, इस विवाद का निर्णय किसी निष्पक्ष व्यक्ति से करवाते हैं।" दरिद्रता देवी ने सहमति जताई और बोलीं — "ठीक है, हम धरती पर चलते हैं और जो पहला मनुष्य हमें दिखाई देगा, वही हमारा न्यायाधीश होगा।"

दोनों देवियाँ धरती पर उतरीं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक किसान दिखाई दिया, जो खेत में हल चला रहा था। उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, और उसके होंठों पर परिश्रम की सच्ची मुस्कान थी। धरती माता के इस पुत्र के भीतर सादगी और गहराई का मेल था। दोनों देवियाँ उसके सामने प्रकट हुईं। किसान पहले तो घबरा गया, क्योंकि उसने एक साथ दो अद्भुत तेजस्वी रूप देखे। फिर वह folded hands से बोला, "मां, मैं आपकी सेवा में कैसे उपयोगी हो सकता हूँ?"

लक्ष्मी देवी ने मुस्कराते हुए कहा — "किसान, हम दोनों में विवाद है कि कौन अधिक सुंदर है। तुम हमें देख रहे हो, अब तुम ही निर्णय करो। लेकिन ध्यान रहे, जब तक तुम न्याय नहीं दोगे, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते।"

किसान के लिए यह स्थिति बड़ी कठिन थी। वह जानता था कि यदि उसने किसी एक के पक्ष में निर्णय दिया, तो दूसरी देवी क्रोधित होकर उसे शाप दे देगी। वह कुछ पल चुप रहा, मिट्टी में पड़े हल को सीधा किया, और आसमान की ओर देखा। फिर बोला — "देवियों, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। आपकी दिव्यता और सुंदरता की तुलना करना मेरे बस की बात नहीं। फिर भी यदि आप आदेश देती हैं, तो मैं कुछ कहने का साहस करता हूँ। दरिद्र देवी, जब आप किसी के घर से विदा होती हैं, तब आपसे सुंदर कोई नहीं लगता। क्योंकि आपके जाने से उस घर में उजाला लौट आता है, मुस्कुराहटें लौट आती हैं। और लक्ष्मी देवी, जब आप किसी के घर में आती हैं, तो आपसे सुंदर कोई नहीं दिखता, क्योंकि आपके आगमन से वहाँ आनंद और ऐश्वर्य का सागर उमड़ पड़ता है।"

यह सुनकर दोनों देवियाँ एक-दूसरे की ओर देखने लगीं। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर लक्ष्मी देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और बोलीं — "किसान, तुम्हारी वाणी में न तो चापलूसी है, न पक्षपात। तुम्हारे शब्दों में सत्य, संतुलन और बुद्धि की गंध है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर सदा मेरे चरण रहेंगे।" दरिद्रता देवी ने भी गंभीर स्वर में कहा — "तुम्हारी निष्पक्षता और समझदारी मुझे प्रिय लगी। तुम्हारे घर में मैं कभी प्रवेश नहीं करूँगी।"

दोनों देवियाँ आकाश मार्ग से लौट गईं। किसान विस्मित रह गया। उसने समझा कि उसने केवल एक कठिन स्थिति से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया था, पर वास्तव में उसने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत सीख लिया — कभी-कभी सही शब्द ही सबसे बड़ा वरदान बन जाते हैं।

उस दिन से किसान का जीवन बदल गया। उसकी फसलें पहले से अधिक लहलहाने लगीं। पशु स्वस्थ रहने लगे, घर में प्रसन्नता और संतोष का वातावरण छा गया। लोग दूर-दूर से उसकी समझदारी और वाणी की प्रशंसा करने आने लगे। जब कोई उससे पूछता कि उसने देवियों को इतना संतुलित उत्तर कैसे दिया, तो वह मुस्कुराकर कहता — "जब मन शांत हो, और बुद्धि सत्य की राह पर चले, तब वाणी अपने आप सही दिशा में बहने लगती है।"

इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हाजिरजवाबी केवल तेज़ जवाब देने की कला नहीं होती, बल्कि वह विवेक और संयम की पराकाष्ठा है। कभी-कभी जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर तर्क या बल से नहीं, बल्कि कोमल वाणी और संतुलित दृष्टिकोण से दिया जाता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है — बुद्धि की विजय।

तरक्की को मुंह चिढ़ा रहे हैं महिला अपराधों के आंकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2023 के महिला अपराधों के आंकड़े देश की तरक्की के आंकड़ों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। देश एक तरफ जहां रक्षा, विज्ञान—तकनीकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में जहां लगातार आगे बढ़ रहा है वहीं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में शर्मसार हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में उससे पिछले दो सालों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरे देश में ऐसे करीब 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए।

वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 4,45,256 और 2021 में 4,28,278 मामले थे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, पश्चिम बंगाल में 34,691 और मध्यप्रदेश में 32,342 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 124.9 अपराध दर के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि इसके बाद राजस्थान 114.8, ओडिशा 112.4, हरियाणा 110.3 और केरल में 86.1 अपराध दर दर्ज की गई।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले सबसे ज्यादा थे, जिनमें 133,676 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 19.7 रही। महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने के 88,605 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 13.1 रही। महिलाओं की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला करने के 83,891 मामले आए जबकि बलात्कार के 29,670 मामले दर्ज किए गए। अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं से बलात्कार के 28,821 मामले आए और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के 849 मामले आए। बलात्कार के प्रयास के 2,796 मामले दर्ज किए गए।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बच्चों से बलात्कार के 40,046 मामले, यौन उत्पीड़न के 22,149 मामले, यौन प्रताड़ना के लिए 2,778 मामले, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के 698 मामले और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत 513 मामले दर्ज किए गए। पुलिस के निपटारा आंकड़ों से पता चला कि पिछले वर्षों से 185,961 मामले जांच के लिए लंबित थे, जबकि 4,48,211 नए मामले दर्ज किए गए और 987 स्थानांतरित किए गए। इस तरह कुल 635,159 मामले थे। एसिड अटैक के 113 मामले दर्ज किए गए।

साल 2012 में दिल्ली में निर्भया के बलात्कार और हत्या के बाद जमीन पर ज्यादा कुछ बदला नहीं दिखता। कठोर कानून मौजूद हैं, पर वे कितने प्रभावी हैं? साल 2022 के लिए उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गये, जो साल 2021 से चार फीसदी ज्यादा थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध का सबसे बड़ा हिस्सा 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.4 फीसदी) के तहत दर्ज हुआ, जबकि सभी अपराधों में 'शील हनन की नीयत से महिलाओं पर हमले' का हिस्सा 18.7 फीसदी था, और 'बलात्कार' 7.1 फीसदी पर रहा।

डब्ल्यूपीएस इंडेक्स (महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक) की 2023 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग साल 2023 में 128वें स्थान पर रही। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और स्वीडन शीर्ष पर रहे, जबकि अफगानिस्तान, यमन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे निचले स्थान पर रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली राजनीतिक हिंसा के मामले में भारत शीर्ष 10 सबसे खराब देशों में शामिल है। मेक्सिको 537 ऐसी घटनाओं के साथ इस सूची में शीर्ष पर है, उसके बाद ब्राज़ील (327) का स्थान है, जबकि भारत इस सूची में 125 घटनाओं (प्रति 100,000 महिलाओं पर) के साथ सातवें स्थान पर है, जहाँ विशेष रूप से राजनीतिक हिंसा के लिए महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) में पाया गया कि 18-49 वर्ष की आयु की 29.3% महिलाओं ने अपने जीवनकाल में पति द्वारा हिंसा का अनुभव किया है। अगर अपराध दर्ज भी हो जाते हैं, तो न्याय धीमा हो सकता है; पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अक्सर पीड़ितों को ही दोषी ठहराते हैं या उनकी गवाही को हतोत्साहित करते हैं। परिणामस्वरूप, कई मामले आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि सांस्कृतिक शर्मिंदगी और प्रतिशोध का डर रिपोर्ट दर्ज कराने में बड़ी बाधाएँ हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कारण पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षा और जागरूकता की कमी, कानूनों का कम प्रभावी कार्यान्वयन और महिलाओं के प्रति समाज की घटती संवेदनशीलता जैसे सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक कारक हैं।

भारत की चुनौती वैश्विक रुझानों के समान और उनसे भी बदतर है। कई देशों की तरह, भारत भी कम रिपोर्टिंग और कलंक से जूझ रहा है। लेकिन गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रह और विशाल जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि अघोषित अपराधों का एक छोटा सा प्रतिशत भी बहुत बड़ी संख्या में तब्दील हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना इस बात पर ज़ोर देती है कि समाधानों में हर देश की हिस्सेदारी है – अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने से लेकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तक। कानूनों और जागरूकता के मामले में भारत में हाल ही में हुए सुधार सकारात्मक हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी कई समकक्षों से पीछे है।

अभियान

मातृत्व का पावन पर्व: अहोई अष्टमी की कथा, परंपरा और भावनात्मक गहराई

भारतीय संस्कृति में हर पर्व और व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि उसमें जीवन के किसी गहरे भाव, सामाजिक संबंध और मानवीय मूल्य की अनुभूति छिपी होती है। इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक है अहोई अष्टमी, जो मातृत्व के सबसे कोमल, संवेदनशील और त्यागमयी रूप को प्रकट करने वाला उत्सव है। यह दिन केवल पूजा या उपवास का नहीं, बल्कि उस ममता की साधना का है जो अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहने को तत्पर रहती है। अहोई अष्टमी का व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है — उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में यह पर्व माताओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा और भावनात्मक समर्पण से मनाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसका स्वरूप बदल गया है, पर इसकी भावना आज भी उतनी ही गहरी है। अब यह व्रत केवल गाँवों या परंपरागत घरों तक सीमित नहीं रहा; शहरी परिवारों और प्रवासी भारतीय समुदायों में भी यह मातृत्व का प्रतीक बनकर फैल गया है। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में यह पर्व अपने सीमित भूगोल से निकलकर अखिल भारतीय उत्सव बन चुका है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्तूबर को मनाया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, अष्टमी तिथि दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से प्रारंभ होकर अगले दिन 14 अक्तूबर को सुबह 11 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। पूजा का शुभ समय शाम 5 बजकर 59 मिनट से लेकर 7 बजकर 14 मिनट तक माना गया है। इस दौरान माताएं अपने संकल्प और श्रद्धा के साथ अहोई माता की पूजा-अर्चना करती हैं।

अहोई अष्टमी व्रत की विशेषता यह है कि यह निर्जला उपवास होता है — इस दिन माताएं पूरे दिन अन्न-जल का त्याग करती हैं। वे सूर्योदय से लेकर रात में तारों या चंद्रमा के दर्शन तक व्रत रखती हैं। यह केवल शरीर का संयम नहीं, बल्कि मातृत्व के उस मानसिक बल का प्रतीक है जो संतान की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करने को

तत्पर रहता है। शाम के समय घर की दीवार या पूजा स्थल पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है, जिसमें आठ कोष्ठक (अष्टमी के प्रतीक) और सेह या सियाह (जो जंगली जानवर या नेवला माना जाता है) का चित्र होता है। पूजा में हलवा, पूरी, पुआ और अन्य पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें अर्घ्य के साथ माता को समर्पित किया जाता है। अहोई अष्टमी की कथा लोक परंपराओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक साहूकार दंपति के सात पुत्र थे। कार्तिक मास की अष्टमी के आठ दिन पहले उसकी पत्नी घर की मरम्मत और सजावट के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय अनजाने में उसके फावड़े से एक सियाह (नेवले) के बच्चे की मृत्यु हो गई। उस सियाह ने क्रोध में आकर साहूकार की पत्नी को श्राप दिया—"जिस प्रकार तूने मेरे बच्चों की हत्या की है, उसी प्रकार तेरे भी सारे बच्चे एक-एक करके मरेंगे।" उस श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। साहूकार के बच्चे एक-एक करके काल के गाल में समा गए। साहूकार दंपति शोक में डूब गया। अंततः साहूकार की पत्नी ने अपने अपराध का प्रायश्चित्त करने का निश्चय किया। वह करुणापूर्वक अहोई माता की उपासना में लीन हो गई। उसने उपवास रखा, माता से क्षमा माँगी और संकल्प किया कि वह हर वर्ष यह व्रत रखेगी ताकि संतान की रक्षा हो सके। उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चात्ताप से प्रसन्न होकर अहोई माता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी संतानें पुनः जीवित हो गईं। उसी दिन से यह व्रत माताओं के लिए संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गया।

इस कथा का गूढ़ संदेश केवल धार्मिक विश्वास में नहीं, बल्कि जीवन के एक शाश्वत सत्य में छिपा है—मां के संकल्प से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। जब एक मां अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है, तो वह अपने आत्मबल, प्रेम और त्याग से ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी बदल देती है। यही कारण है कि अहोई अष्टमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मातृत्व का उत्सव है।

इस दिन पूजा के बाद माताएं तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। कुछ स्थानों पर तारे देख कर व्रत तोड़ा जाता है, तो कुछ जगहों पर चंद्र दर्शन के बाद। पूजा में प्रयुक्त मिट्टी का करवा जल से भरा जाता है और उसके मुंह को घास या मिट्टी से बंद किया जाता है। यह करवा संकल्प, धैर्य और ममता का प्रतीक माना जाता है। व्रत समाप्त होने पर माताएं अपनी सास या किसी वृद्ध महिला के चरण स्पर्श करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं कि उनकी संतानें सदा स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहें। अहोई अष्टमी का यह पर्व समाज में परिवार के प्रति समर्पण, एकता और करुणा की भावना को भी बढ़ाता है। जब पूरा परिवार मां के व्रत में सहभागी होता है, तो घर का वातावरण पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम से भर उठता है। छोटे-छोटे बच्चे जब अपनी माताओं को पूजा करते देखते हैं, तो उनके भीतर भी यह भाव अंकुरित होता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि परस्पर प्रेम और सुरक्षा है।

यह व्रत अंततः यही सिखाता है कि मां का प्रेम किसी उपहार या वचन से नहीं मापा जा सकता। उसकी प्रार्थना, उसका त्याग और उसकी निःस्वार्थ भावना ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। अहोई अष्टमी उस मातृत्व का अभिनंदन है, जो अपनी संतान के लिए जल, अन्न, आराम सब कुछ त्यागकर भी मुस्कुराती है—क्योंकि उसके लिए अपने बच्चों का जीवन ही उसका सच्चा उत्सव है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

श्री अश्विनी वैष्णव ने वलसाड में आरपीएफ स्थापना दिवस परेड में भाग लिया और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार विजेताआरपीएफ कर्मियों को किया सम्मानित

माननीय मंत्री ने भारतीय रेल में हो रहे व्यापक परिवर्तन पर प्रकाश डाला; आरपीएफ के लिए उन्नत तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण पहल की घोषणा की

(जीएनएस)। माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 13 अक्टूबर, 2025 को आरपीएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, वलसाड में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों की जान बचाने में उनके साहसी प्रयासों के लिए 41 आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्हें सराहनीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक, जीवन रक्षा पदक आदि से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार देश के रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा में आरपीएफ की अनुकरणीय सेवा को दर्शाते हैं तथा बल के अन्य सदस्यों को नए जोश के साथ अपने समर्पित प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने आरपीएफ परेड की औपचारिक सलामी भी ली, जो अनुशासन और प्रतिबद्धता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था। मंत्री ने परेड के दौरान कर्मियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन, सटीकता और समर्पण के उच्च स्तर की सराहना की।

अपने संबोधन में श्री वैष्णव ने आरपीएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई दी और यात्रियों एवं रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की। मंत्री महोदय ने हाल ही में हुए महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में आरपीएफ की उल्लेखनीय सेवा की भी सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। पिछले 11 वर्षों में, लगभग 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियाँ बिछाई गई हैं और 99% रेलवे नेटवर्क (लगभग 60,000 किलोमीटर) का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 150 वंदे भारत और 30 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जो यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से 110 स्टेशनों का उद्घाटन हो चुका है और शेष पर काम तेज़ी से प्रगति पर है।

उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीज़न की मांग को पूरा करने के लिए दिवाली और छठ के लिए रिकॉर्ड संख्या में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो रही है। श्री वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि कवच प्रणाली को दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर तेज़ी से लागू किया जा रहा है और यह उन्नत चरण पर है। कवच को 1200 इंजनों पर लगाया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि हर साल लगभग 7000 कोच बनाए जा रहे हैं, जबकि लोगों की सुविधा के लिए 3500 सामान्य कोच भी जोड़े गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि रेलवे सुरक्षा बल में आधुनिक प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है और इस दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वलसाड के संसद सदस्य श्री धवल पटेल; वलसाड के विधायक श्री भरतभाई पटेल; कपराडा के विधायक श्री जीतूभाई चौधरी; उमरगाम के विधायक श्री रमणलाल पाटकर; आरपीएफ की महानिदेशक श्रीमती सोनाली मिश्रा; पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता; पश्चिम रेलवे के पुलिस महानिरीक्षक / प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अजय सदानी; मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह और पश्चिम रेलवे के मुख्यालय और मंडल के अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे।

आरपीएफ स्थापना दिवस परेड आरपीएफ सदस्यों और उनके परिवारों द्वारा मनाई जाती है। यह जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि का दिन है। आरपीएफ एक करुणामयी शक्ति के रूप में उभरी है क्योंकि यह रेलवे के संपर्क में आने वाली महिलाओं, बच्चों, बीमारों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य लोगों की सहायता करती रही है। यह बल रेल यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत है। परिवहन सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर, आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करके, मानव तस्करी सहित अपराधों से लड़कर, अपराधों का पता लगाने में पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करके, तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करके, यह राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड में एक महत्वपूर्ण हितधारक बन गया है।

रेलवे सुरक्षा बल ने "सेवा ही संकल्प" के उद्देश्य को साकार करने के लिए राष्ट्र और नागरिकों की सेवा के लिए पूरी लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ खुद को समर्पित किया है और अपने आदर्श वाक्य "यशो लभस्व" अर्थात "महिमा प्राप्त करें" की दिशा में काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

आरएसएस पर बैन की मांग से कर्नाटक में बढ़ा राजनीतिक तनाव, सिद्धारमैया के बेटे बोले – 'तालिबान जैसी है आरएसएस की सोच', मुख्यमंत्री ने सरकारी परिसरों में शाखाओं की जांच के दिए आदेश

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में सोमवार को एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तुलना तालिबान से करते हुए राज्य में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। यतींद्र ने कहा कि आरएसएस हिंदू धर्म को उसी कठोर और सत्तावादी तरीके से लागू करना चाहता है, जैसे तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को बलपूर्वक लागू करता है। उनके इस बयान के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा सामाजिक सद्भाव के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा, "आरएसएस महिलाओं की स्वतंत्रता, धार्मिक समानता और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ काम करता है। यह संगठन समाज में विभाजन पैदा करने का काम करता है। यदि तालिबान इस्लाम के नाम पर एकपक्षीय सोच थोपना चाहता है, तो आरएसएस भी हिंदू धर्म की व्याख्या को अपने तरीके से थोपने की कोशिश कर रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस को कानूनी ढांचे के भीतर लाना आवश्यक है। "यह संगठन वर्षों से एक गैर-पंजीकृत इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसे कई कानूनी जिम्मेदारियों से छूट मिली हुई है। अब समय आ गया है कि इसे एक पंजीकृत संस्था बनाया जाए ताकि इसकी गतिविधियाँ कानून के अधीन रहें।"

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार सरकारी परिसरों और संस्थानों में किसी भी राजनीतिक या वैचारिक संगठन की गतिविधियों की अनुमति नहीं देती। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि यह जांच की जाए कि कहीं आरएसएस सरकारी कार्यालयों, स्कूलों या विश्वविद्यालय परिसरों में अपनी शाखाएं तो नहीं चला रहा।

सिद्धारमैया ने कहा, "मुझे जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर सरकारी स्कूलों या कार्यालय परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगाई जा रही हैं। यह जांच का विषय है। हमने मुख्य सचिव को तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करने का आदेश दिया है, जहाँ राज्य सरकार ने किसी भी धार्मिक या राजनीतिक संगठन को सरकारी परिसरों में गतिविधियाँ करने से प्रतिबंधित किया है। यदि ज़रूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी इसी तरह के कदम उठाए जाएंगे।"

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में आरएसएस की शाखाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि "सरकारी संस्थान धर्मनिरपेक्ष चरित्र के प्रतीक हैं। यहाँ किसी भी धार्मिक या वैचारिक संगठन की गतिविधि संविधान की भावना के खिलाफ है।"

यतींद्र सिद्धारमैया के बयान के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता सीटी रवि ने कहा, "आरएसएस इस देश की आत्मा है। यह संगठन राष्ट्रनिर्माण के कार्य में लगा है। जिन लोगों की विचारधारा वामपंथ और वोट बैंक की राजनीति में उलझी है, वे ही इसे तालिबान कह सकते हैं। यह कांग्रेस की घबराहट का परिणाम है, क्योंकि जनता अब उनकी राजनीति को समझ चुकी है।"

वहीं, जनता दल (एस) ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "कर्नाटक में महंगाई, बिजली संकट और किसानों की परेशानियाँ चरम पर हैं। लेकिन सरकार उन पर ध्यान देने के बजाय आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रही है। यह जनता को भ्रमित करने की कोशिश है।"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यतींद्र का यह बयान केवल विचारधारात्मक टकराव नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर की रणनीति का हिस्सा भी है। कांग्रेस राज्य में हिंदुत्व राजनीति के प्रभाव को सीमित करने के लिए आरएसएस के खिलाफ एक वैचारिक अभियान चलाने की तैयारी में है।

वहीं, आरएसएस के स्थानीय प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। एक वरिष्ठ स्वयंसेवक ने कहा, "हम किसी भी सरकारी परिसर में जबरन शाखा नहीं लगाते। लोग स्वयं जुड़ते हैं क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (FIEO) प्रेस विज्ञप्ति

VGRC के तहत आयोजित अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट से 500 करोड़ की निर्यात संभावनाओं को मिला नया आयाम

(जीएनएस)। गांधीनगर : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (FIEO) और गुजरात सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के RAMP प्रोजेक्ट के तहत, गुजरात सरकार के MSME विभाग और iNDEXTb के सहयोग से एक अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 9-10 अक्टूबर 2025 को गणपत विश्वविद्यालय, मेहसाणा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (उत्तर गुजरात) के भाग रूप में आयोजित हुआ।

उद्योग प्रतिनिधियों की ओर से इस दो दिवसीय कार्यक्रम को शानदार प्रतिसाद मिला। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (FIEO) और गुजरात सरकार के संयुक्त आयोजन में 9 से 10 अक्टूबर 2025 को मेहसाणा में अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट सफलतापूर्वक आयोजित हुई। इस आयोजन में कुल 17 देशों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख देश अमेरिका, जर्मनी, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, मिस्र, इथियोपिया, घाना, तंजानिया, युगांडा, भूटान, ओमान, बहरीन, नेपाल, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन और बोत्सवाना शामिल थे।

कार्यक्रम में 40 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और गुजरात सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से आए 850 से अधिक स्थानीय विक्रेताओं ने भाग लिया। दो दिनों में कुल 2,200 से अधिक व्यावसायिक बैठकों का आयोजन किया गया और 350 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अंतरराष्ट्रीय मीट के परिणामस्वरूप लगभग 500 करोड़ से अधिक की एक्सपोर्ट एन्क्वारीज़ प्राप्त हुई, जिससे गुजरात की निर्यात संभावनाओं को नया प्रोत्साहन मिला।

डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) श्री अजय भादू (IAS) और गुजरात सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) आयुक्त श्री संदीप जे. सागले ने बायर-सेलर मीट में उपस्थित होकर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों से संवाद किया और वैश्विक व्यापारिक संबंधों को गति देने तथा गुजरात की निर्यात क्षमता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की।

FIEO के अध्यक्ष श्री एस. सी. रालहा ने बताया कि दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट में वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे प्रमुख क्षेत्र केंद्र में रहे। यह आयोजन वैश्विक व्यापारिक संपर्कों को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ। साथ ही, इसने गुजरात को एक अग्रणी निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

'लाडकी बहन' योजना से खाली हुई महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी, फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की कई योजनाएं कीं बंद, विपक्ष बोला – 'जनता की भलाई ठप, सत्ता की सजावट चालू'

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विवाद तब खड़ा हो गया जब यह खुलासा हुआ कि 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' यानी 'लाडकी बहन योजना' के कारण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो गई है। चुनावी साल में महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने वाली इस योजना ने सरकार के खजाने पर इतना बोझ डाल दिया कि अब राज्य में कई अन्य विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं ठप पड़ गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार ने सत्ता संभालने के बाद एकनाथ शिंदे के कार्यकाल की आठ से अधिक बड़ी योजनाओं को बंद कर दिया है। इनमें सामाजिक कल्याण, शिक्षा, रोजगार और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार का पूरा ध्यान फिलहाल वित्तीय संतुलन बहाल करने और बजट घाटे को नियंत्रित करने पर है, जबकि विपक्ष इसे जनता से विश्वासघात बता रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने इस मुद्दे पर सोमवार को सोशल मीडिया पर तीखा हमला किया। उन्होंने लिखा, "महायुति सरकार की तिजोरी लाडकी बहन योजना के कारण खाली हो चुकी है। सरकार ने आम जनता की भलाई के लिए शुरू की गई योजनाओं को बंद कर दिया है। सहयोगी दलों के नेता चुप हैं, और जो बोल रहे हैं, वे सिर्फ बुलेट ट्रेन की गति की तारीफ कर रहे हैं, जबकि गांवों में लोग बेरोजगार और परेशान हैं।"

दानवे ने आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार ने शिंदे के समय की आठ प्रमुख योजनाओं को पहले ही खत्म कर दिया है। इनमें 'आनंदाचा शिधा योजना' (गरीब परिवारों को कम दाम पर राशन), '1 रुपये में फसल बीमा', 'स्वच्छता मॉनीटर योजना', 'एक राज्य एक गणवेश', 'प्यारे भाई के लिए अप्रेंटिसशिप योजना', 'योजना दूत' और 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब 'मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय, सुंदर विद्यालय योजना' भी बंद होने की कगार पर है। 'मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय, सुंदर विद्यालय योजना' शिंदे सरकार की महत्वाकांक्षी शिक्षा परियोजनाओं में से एक थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, उनकी इमारतों की मरम्मत करना, और छात्रों को स्वच्छ व प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना था। 5 दिसंबर 2023 को शुरू की गई इस योजना के तहत स्कूलों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं, जिसमें विजेताओं को लाखों रुपए के पुरस्कार दिए गए थे। लेकिन अब अक्टूबर 2025 तक इस योजना में कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं हुआ है। न तो इसके लिए बजट आवंटित किया गया और न ही जिला स्तर पर कोई समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, वित्त विभाग ने इस योजना के लिए नया फंड जारी करने से इंकार कर दिया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि योजना पर अनौपचारिक रूप से रोक लगा दी गई है। रकारी सूत्रों के अनुसार, 'लाडकी बहन योजना' के तहत राज्य की 1.7 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना पर वार्षिक लगभग 48,000 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है, जिससे राज्य का राजकोषीय घाटा 2024-25 में 3.8% तक पहुंच गया है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि यह सीमा वित्तीय अनुशासन के मानकों से कहीं अधिक है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "लाडकी बहन योजना राजनीतिक रूप से लोकप्रिय है, लेकिन आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं। हमने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि इसके खर्च को नियंत्रित नहीं किया गया तो अन्य सामाजिक योजनाएं प्रभावित होंगी।

इन्वेस्ट यूपी का पुनर्गठन: निवेशक केंद्रित, विशेषज्ञता आधारित और औद्योगिक विकास में नई ऊँचाई

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में संस्था के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पुनर्गठन का उद्देश्य इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता आधारित और निवेशक केंद्रित संस्था बनाना है। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ सेल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी को एक 'एकल निवेश सुविधा एजेंसी' के रूप में सशक्त किया जाएगा। यह एजेंसी न केवल निवेश आकर्षित करेगी, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी निगरानी भी करेगी। बैठक में 11 महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक पदों को स्वीकृति दी गई, जबकि दो पीसीएस अधिकारियों को संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। साथ ही भूमि बैंक प्रकोष्ठ भी गठित किया जाएगा, जिसमें दो पीसीएस अधिकारी तैनात रहेंगे।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 में लगभग 4,000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुईं, जिससे कुल संख्या 27,000 तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' मंत्र के सफल क्रियान्वयन का परिणाम बताया, जिससे राज्य का औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत हुआ है। निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के माध्यम से औद्योगिक निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई सुविधाएँ जोड़ी जा रही हैं। इसमें सिंगल साइन-ऑन, डायनेमिक एप्लीकेशन सिस्टम, एआई चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे आवेदन, स्वीकृति और प्रोत्साहन प्रक्रिया में समय 30 प्रतिशत और दस्तावेजी औपचारिकताओं में 50 प्रतिशत तक कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश अब सिर्फ नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि "ग्राउंड लेवल डिलीवरी" का उदाहरण बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक निवेशकों से सक्रिय संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ताइवान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के निवेशक शामिल हैं। उन्होंने 'सेफ सिटी' की तर्ज पर 'सेफ इंडस्ट्री' की अवधारणा लागू करने के निर्देश दिए, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी नियमित रूप से निवेशकों से संवाद करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

दुर्गापुर MBBS छात्रा दुष्कर्म मामला : सभी पांच आरोपी गिरफ्तार, महिला आयोग ने सीएम को लिखा पत्र

(जीएनएस)। कोलकाता/दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक MBBS छात्रा के साथ हुए घिनौने गैंगरेप मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। पुलिस ने सोमवार को शेष दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस मामले के सभी पांच आरोपी अब कानून के घेरे में हैं। इससे पहले रविवार को तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित की। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी पीड़िता पर हमला करने के समय अलग-अलग स्थानों पर मौजूद थे और घटना की योजना पहले से बनाई गई थी।

पीड़िता के पिता ने घटना की सटीक समयरेखा साझा करते हुए कहा कि उनके साथ हुई घटना शुक्रवार, 10 अक्टूबर की रात 8 बजे से 9 बजे के बीच हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने घटना को आधी रात के बाद बताकर एक असंवेदनशील टिप्पणी की थी। पीड़िता के पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद एक महिला होने के बावजूद यह टिप्पणी करती हैं, जो पीड़िता और परिवार के लिए मानसिक पीड़ा बढ़ाने वाला है। उन्होंने राज्य प्रशासन से न्याय सुनिश्चित करने की अपील की।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि पीड़िता की पढ़ाई बाधित न हो और उसे न्याय मिलने तक हर संभव सहायता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है। आयोग ने प्रशासन से पीड़िता की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा में निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने की मांग की। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में पूरी गंभीरता से जुटे हुए हैं। पुलिस ने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और आरोपी जल्द से जल्द अदालत के समक्ष पेश किए जाएंगे। इस बीच समाज और छात्र समुदाय में भी इस घटना को लेकर रोष है और न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता पर पूरे देश में बहस छेड़ दी है। राज्य सरकार और प्रशासन अब तक की कार्रवाई को लेकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घटना का संपूर्ण कानूनी निपटारा हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। साथ ही, यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएँ, ताकि भविष्य में किसी भी महिला को इस तरह के अपराध का सामना न करना पड़े।

विकास सप्ताह : 14 अक्टूबर, कृषि विकास दिवस

विकास सप्ताह के तहत गुजरात में 14-15 अक्टूबर को आयोजित होगा 'रबी कृषि महोत्सव-2025'

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल पंचमहाल-गोधरा के छबनपुर गांव में करेंगे राज्यव्यापी शुभारंभ

कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल :-

- राज्य में 261 स्थानों पर आयोजित होने वाले जिला और तहसील स्तरीय कार्यक्रमों का मंत्री, सांसद और विधायक सहित पदाधिकारी करेंगे शुभारंभ
- महोत्सव में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता वितरित की जाएगी
- दो दिवसीय रबी कृषि महोत्सव में गुजरात के 3 लाख से अधिक किसान लेंगे हिस्सा
- महोत्सव के दौरान विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे निःशुल्क पशु स्वास्थ्य

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणादायी जनसेवा यात्रा के 24 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समग्र गुजरात में 7 से 15 अक्टूबर के दौरान विभिन्न थीमों पर आधारित 'विकास सप्ताह' मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 14 अक्टूबर को 'कृषि विकास दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

कृषि विकास दिवस के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से 14 और 15 अक्टूबर को 'रबी कृषि महोत्सव-2025' का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को मौजूदा समय के अनुरूप कृषि पद्धतियों, टेक्नोलॉजी और नवीन दृष्टिकोण से परिचित कराना है। कृषि क्षेत्र और राज्य के किसानों को समर्पित 'कृषि विकास दिवस' के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल पंचमहाल-गोधरा के छबनपुर गांव में राज्यव्यापी 'रबी कृषि महोत्सव-2025' का शुभारंभ करेंगे।

कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल ने रबी कृषि महोत्सव-2025 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि विकास सप्ताह के तहत 14 और 15 अक्टूबर को राज्य में कुल 261 स्थानों पर जिला और तहसील स्तरीय रबी कृषि महोत्सव-2025 का आयोजन किया जाएगा। गुजरात सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों सहित विभिन्न पदाधिकारी और उच्च अधिकारी जिला और तहसील स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इस दो दिवसीय रबी कृषि महोत्सव में गुजरात के लगभग 3 लाख से अधिक किसान हिस्सा लेंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि रबी कृषि महोत्सव के दौरान गुजरात सरकार राज्य के प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों को विशेष रूप से सम्मानित करेगी। इसके अलावा, कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 500 करोड़ रुपए की सहायता के मंजूरी पत्र और सहायता आदेश का भी वितरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य के कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ किसानों को उनके क्षेत्रों में रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसलों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन के अलावा प्राकृतिक खेती और बागवानी फसलों में नवीनतम टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों पर भी मार्गदर्शन देंगे। साथ ही, प्रगतिशील किसानों और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के प्रतिनिधियों द्वारा भी विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिए जाएंगे।

इस महोत्सव में किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और प्राकृतिक खेती की पद्धति के संबंध में जागरूक करने के लिए फसल परिचर्चा, नई टेक्नोलॉजी पर आधारित कृषि प्रदर्शनी और किसान-उन्मुख विभिन्न सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य की सभी तहसीलों में किसान प्राकृतिक कृषि के मॉडल फॉर्म का दौरा करेंगे। विशेषज्ञों एवं प्रगतिशील किसानों द्वारा खेती से जुड़ी किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दो दिनों के दौरान पशुपालन विभाग ने भी विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है, जिनका पशुपालक लाभ उठा सकते हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि रबी कृषि महोत्सव कार्यक्रम स्थलों पर प्रगतिशील किसानों के उत्पादों, प्राकृतिक खेती के आयामों, ड्रोन जैसी आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि और मृदा परीक्षण तथा किसान उपयोगी अनुसंधानों सहित नए जमाने के उर्वरकों के इस्तेमाल को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों सहित कुल 2800 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लैंड सीडिंग (भू-आलेखों का सत्यापन), किसान पंजीकरण के अंतर्गत ई-केवाईसी और स्व-पंजीकरण से संबंधित स्टॉल तथा कृषि यंत्रीकरण और कृषि प्रसंस्करण के यंत्रों एवं औजारों के स्टॉल भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2005 में कृषि महोत्सव की एक नई परंपरा शुरू की थी, ताकि कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों के साथ सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ ही नई खेत पद्धतियों से अवगत करा सकें। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई इस परंपरा को आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री श्री राघवजी पटेल बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।

विकास सप्ताह : 14 अक्टूबर, कृषि विकास दिवस

प्राकृतिक खेती ने डांग की मंगीबेन को बनाया लखपति दीदी, श्रीअन्न से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर अन्य महिलाओं को दी प्रेरणा

- **प्राकृतिक कृषि से आई समृद्धि : मंगीबेन ने पहले ही महीने नागली (श्रीअन्न) से बने 15,000 रुपए के उत्पाद बेचे, आज उनकी यूनिट प्रतिमाह 60,000 रुपए के उत्पाद बेचती है**
- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में प्राकृतिक खेती को मिला बढ़ावा**

(जीएनएस)। गांधीनगर : 7 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 24 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात 7 से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मना रहा है। इसके अंतर्गत राज्य में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए 14 अक्टूबर का दिन 'कृषि विकास दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है, इसके परिणामस्वरूप राज्य के किसान कृषि की टिकाऊ पद्धति अपनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। आज, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।

'आपणुं डांग, प्राकृतिक डांग' अभियान से आदिवासी किसानों के जीवन में आया बदलाव

जब भी प्राकृतिक कृषि की बात होती है, एक अभियान का नाम अनायास ही जुबान पर आता है, वो है 'आपणुं डांग, प्राकृतिक डांग' यानी 'हमारा डांग, प्राकृतिक डांग।' इस अभियान के माध्यम से वर्ष 2021 में प्राकृतिक सौंदर्य से लकदक डांग जिले को संपूर्ण रूप से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित किया गया था। तब से, यह पहल आदिवासी किसानों के जीवन में एक शानदार बदलाव लेकर आई है। इस बदलाव का चेहरा बनकर उभरी हैं आहवा जिले के धवलीदोड़ गांव की मंगीबेन, जो आज प्राकृतिक खेती अपनाकर लखपति दीदी बन गई हैं।

डांग की मंगीबेन का साहसिक प्रयास लाया रंग : स्थानीय श्रीअन्न-नागली से बनाए मूल्यवर्धित उत्पाद

मंगीबेन का साहस से समृद्धि तक सफर दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणादायी बन गया है। मिशन मंगलम (एनआरएलएम) के तहत फील्ड को-ऑर्डिनेटर ने मंगीबेन को स्वयं सहायता समूह (एसएचओ) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। डांग जैसे वन क्षेत्र और वहां की समृद्ध वन उपज के महत्व को समझते हुए मंगीबेन ने साहस जुटाकर एक नया उद्यम शुरू किया। डांग में उगाए जाने वाले श्रीअन्न नागली (रागी की एक किस्म) को बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। इसके स्वास्थ्य लाभ और बाजार संभावनाओं को ध्यान में रखकर मंगीबेन ने नागली की खेती और प्रसंस्करण की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने समूह के साथ मिलकर नागली से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की शुरुआत की।

एक खेतिहर मजदूर से उद्यमी बनीं मंगीबेन

स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से पहले मंगीबेन एक सीजनल यानी मौसमी खेतिहर मजदूर के रूप में मनरेगा के तहत काम करती थीं। मंगीबेन के जीवन में एक नया और सुखद मोड़ तब आया, जब उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरएसईटीआई) से श्रीअन्न के प्रसंस्करण का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने नागली आटा, लड्डू, कुकीज और स्वास्थ्यप्रद मिश्रण बनाना सीखा और छोटे पैमाने पर अपना एक उद्योग शुरू किया। जब गुजरात सरकार ने डांग को पूरी तरह से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित किया, तब मंगीबेन ने नागली की ऑर्गेनिक (जैविक) खेती करने का रास्ता चुना। टिकाऊ खेती से उत्पादों की न्यूट्रीशन वैल्यू यानी पोषण मूल्य तो बढ़ा ही, साथ ही उनका बाजार मूल्य भी बढ़ गया।

पहले ही महीने बेचे 15,000 रुपए के उत्पाद, आज उनकी यूनिट की बिक्री प्रतिमाह 60,000 रुपए है

मंगीबेन ने उद्योग शुरू करने के पहले ही महीने में 15,000 रुपए के उत्पाद बेचे। इसके बाद, उन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह से 10 और महिलाओं को अपनी इस गतिविधि में शामिल किया। आज, उनकी यूनिट प्रतिमाह 60,000 रुपए तक के नागली के उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करती है और 20,000 रुपए की मासिक आय अर्जित करती है। सरकार के सहयोग से वे विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में हिस्सा लेती हैं, बाजार का विस्तार करती हैं और प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय मिशन के तहत ब्रांडिंग और प्रमोशन की पहलों का लाभ प्राप्त करती हैं। मंगीबेन का खेतिहर मजदूर से उद्यमी बनने तक का सफर, लखपति दीदी की पहल को भी उजागर करता है। उनका यह सफर दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक खेती का रास्ता डांग की महिलाओं के लिए नियमित रोजगार का माध्यम बन गया है और दूसरी महिलाओं को भी इस दिशा में काम करने की प्रेरणा दी है। इतना ही नहीं, यह स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी के जरिए विकास का टिकाऊ मॉडल भी दर्शाता है।

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09429/09430 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09429 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 16 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रति गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 08:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09430 गोरखपुर-साबरमती त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल गोरखपुर से 17 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रति शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को दोपहर 13:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 15:30 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी,उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09431/09432 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (28 फेरे)

ट्रेन संख्या 09431 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 14 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:05 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 08:00 बजे बेगूसराय पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09432 बेगूसराय-साबरमती अनारक्षित स्पेशल बेगूसराय से 16 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 05:00 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं.,ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्ज़ापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र जं., सोनपुर, हाजीपुर एवं बरौनी जं. स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया गया

(जीएनएस)। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माणाधीन बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। उनके साथ वलसाड के सांसद श्री धवल पटेल और गणदेवी के विधायक श्री नरेश पटेल भी थे।

इस दौरान, मंत्री ने बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पर चल रहे निर्माण और ट्रैक बिछाने के कार्यों की समीक्षा की।

A. बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन

बिलिमोरा शहर आम के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। स्टेशन के फसाड का डिज़ाइन आम के बागानों से प्रेरित है, जो शहर की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आंतरिक और प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्र को पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है। फॉल्स सीलिंग को एंटी-वाइब्रेशन हैंगर से लगाया गया है ताकि ट्रेनों की तेज गति से होने वाले कंपन का असर फिटिंग्स पर न पड़े। स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि वेटिंग लाउंज, नर्सरी, शौचालय, रिटेल आउटलेट आदि। विभिन्न स्तरों पर सहज आवागमन के लिए कई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और बच्चों वाले परिवारों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्टेशन परिसर में हरियाली और ताजगीपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ ज़ोन, बसों, कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग, ईवी पार्किंग आदि की योजना बनाई गई है।

सुविधा और स्थिरता को मिलाते हुए, स्टेशन में IGBC (इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल) की कई विशेषताएँ शामिल की गई हैं, जैसे कि पानी का कुशल उपयोग, वर्षा जल संचयन, लो-फ्लो सैनिटरी फिटिंग्स, आंतरिक हिस्सों में कम गर्मी प्रवेश, कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वाले पेंट आदि।

बिलिमोरा के पास केसली गाँव में, नवसारी जिले की अंबिका नदी के किनारे स्थित, यह स्टेशन विभिन्न परिवहन माध्यमों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हैः

- बिलिमोरा रेलवे स्टेशनः 6 कि.मी.
- बिलिमोरा बस डिपोः 6 कि.मी.
- राष्ट्रीय राजमार्ग NH-360ः 2.5 कि.मी.

स्टेशन की मुख्य विशेषताएँः

- कुल निर्मित क्षेत्रफलः 38,394 वर्ग मीटर
- स्टेशन भवन में दो स्तर शामिल हैंः
  ग्राउंड कम कांसॉर्स स्तरः पार्किंग, पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ, पैदल यात्री प्लाज़ा, सुरक्षा जांच चौकियां, वेटिंग लाउंज, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, सीढ़ियाँ, कियोस्क, टिकटिंग काउंटर आदि।
- प्लेटफ़ॉर्म स्तरः दो प्लेटफ़ॉर्म और चार ट्रैक
- हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए 425 मीटर लंबा प्लेटफ़ॉर्म

स्टेशन की प्रगति

रेल और प्लेटफ़ॉर्म स्लैब कास्टिंग का कार्य तथा बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल स्टील का कार्य पूरा हो चुका है। आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और MEP (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग) कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

B. बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का ट्रैक निर्माण कार्य

बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पर आरसी ट्रैक बेड निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुके हैं और रेल लेइंग कार (RLC) का उपयोग करके अस्थायी ट्रैक की स्थापना सक्रिय रूप से प्रगति पर है।

रेल लेइंग कार ट्रैक कंस्ट्रक्शन बेस (TCB) से 200-मीटर वेल्डेड रेल पैनलों को स्थापना स्थल तक ले जाने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे रेल पैनलों को यांत्रिक रूप से संभालने और रखने में आसानी होती है और मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है।

320 कि.मी./घंटा की गति पर ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण की सटीकता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। उच्चतम विश्वसनीयता और सटीकता वाले अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण तैनात किए जाते हैं, और सभी सर्वेक्षण चरणों का बहु-स्तरीय सत्यापन किया जाता है। मामूली निर्माण भिन्नताओं की प्रभावी भरपाई के लिए रेफरेंस पिन (reference pin) सर्वे और रिग्रेशन एनालिसिस विधियों को अपनाया जाता है।

बिलिमोरा स्टेशन में दो लूप लाइनें हैं, जिनमें चार 18 में से 1 टर्नआउट्स मूवेबल क्रॉसिंग्स के साथ और दो 18 में से 1 क्रॉसओवर्स शामिल हैं। मुख्य लाइन 12 में से 1 टर्नआउट के माध्यम से शाखाबद्ध होती है ताकि कन्फर्मेशन कार बेस को समायोजित किया जा सके।

C. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति (10 अक्टूबर 2025 तक)

भारत का पहला 508 कि.मी. लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन है।

- 508 कि.मी. में से, 325 कि.मी. वायाडक्ट और 400 कि.मी. पियर का काम पूरा हो चुका है
- 17 नदी पुल, 05 PSC (प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट) ब्रिज और 10 स्टील ब्रिज पूरे हो चुके हैं
- 216 कि.मी. क्षेत्र में 4 लाख से अधिक नॉइज़ बैरियर लगाए गए हैं
- 217 ट्रैक कि.मी. RC ट्रैक बेड का निर्माण पूरा हो चुका है
- लगभग 57 रूट कि.मी. में 2300 से अधिक OHE मास्ट लगाए जा चुके हैं
- पालघर जिले में 07 पहाड़ी सुरंगों पर खुदाई का काम प्रगति पर है
- BKC और शिलफाटा (महाराष्ट्र) के बीच 21 कि.मी. टनल में से 5 कि.मी. NATM टनल की खुदाई हो चुकी है
- सूरत और अहमदाबाद में रोलिंग स्टॉक डिपो का निर्माण प्रगति पर है
- गुजरात के सभी स्टेशनों पर सुपरस्ट्रक्चर का कार्य उन्नत चरण में है। महाराष्ट्र में तीनो एलिवेटेड स्टेशन का कार्य शुरू हो गया है तथा मुंबई अंडरग्राउंड स्टेशन पर बेस स्लैब कास्टिंग प्रगति पर है

आंबलियासन – विजापुर रेल खंड पर स्पीड ट्रायल दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को

सभी से रेल पटरी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर आंबलियासन से विजापुर के बीच गेज परिवर्तन का कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस कार्य के अंतर्गत नव-निर्मित रेल पटरी पर दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 को सायं 18.00 बजे से किमी 87/1 से किमी 46/2 के बीच अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल किया जाएगा।

स्पीड ट्रायल रेलवे की एक अनिवार्य तकनीकी प्रक्रिया है, जो रेल परिचालन शुरू करने से पूर्व ट्रैक की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं स्थिरता की जांच के लिए की जाती है। इस दौरान ट्रैक पर विभागीय ट्रेनें, माप यंत्र और तकनीकी टीमें कार्यरत रहेंगी। इसलिए आम जनता, मजदूरों, किसानों एवं स्थानीय निवासियों से विशेष अनुरोध है कि वे रेलवे ट्रैक के समीप न जाएँ, ट्रैक को किसी भी स्थिति में पार न करें, तथा बच्चों और पशुओं को रेल लाइन से दूर रखें। सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिकोण से सभी से सहयोग की अपेक्षा है ताकि यह कार्य सुरक्षित, सफल एवं समय पर पूर्ण हो सके। यह गेज परिवर्तन परियोजना क्षेत्र की जनता को बेहतर रेल कनेक्टिविटी और विकास का नया आयाम प्रदान करेगी।

दक्षिण अफ्रीका में बस दुर्घटना: पर्वतीय इलाके में 42 लोगों की मौत

(जीएनएस)। जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र में रविवार को हुई एक भयंकर बस दुर्घटना में कम से कम 42 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना राजधानी प्रिटोरिया से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में, लुई ट्रिचर्ड शहर के पास एन1 राजमार्ग पर हुई। प्रांतीय अधिकारियों के अनुसार बस एक खड़े पर्वतीय दर्रे के पास सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी।

सड़क यातायात प्रबंधन निगम के प्रवक्ता साइमन जवाने ने बताया कि अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है, लेकिन घायलों और बस में सवार कुल यात्रियों की संख्या की जांच अभी जारी है। घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है।

लिम्पोपो प्रांत की सरकार के बयान में कहा गया कि दुर्घटना में मारे गए यात्रियों में जिम्बाब्वे और मलावी के नागरिक शामिल होने की संभावना है, जो अपने देश लौट रहे थे। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि दुर्घटना का कारण क्या था। स्थानीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसियां घटना स्थल पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। इस दुर्घटना ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और पर्वतीय मार्गों पर यात्रा की जोखिमों पर फिर से सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने यात्रियों और परिवहन कंपनियों से सुरक्षित और सावधानीपूर्वक यात्रा करने की अपील की है।